स्वास्थ्य : साझा सरोकार

अभय शुक्ला व अनन्त फड़के

19 मई 2000 के दिन ठाणे ज़िले के एक आदिवासी तालुका दहाणु में 200 से ज़्यादा लोग ज्ञापन पत्र और बैनर लिए सड़कों पर उतर आए। इन बैनरों पर लिखे नारे अनूठे थे : *''स्वास्थ्य संरक्षण हमारा अधिकार, गैरज़रूरी इंजेक्शन देना बन्द करो, कोरा नमकीन पानी नहीं तो और सेलाइन क्या है? सरकारी अस्पतालों से ही सभी दवाइयां मिलनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज मिलना चाहिए....''* और भी न जाने कितने नारे थे।

अजब नारे!

ये लोग कस्बे के दोनों मुख्य रास्तों पर स्थित सभी निजी दवाखानों पर गए। कुछ गैर डिग्री धारी डॉक्टरों ने अपने दवाखाने बन्द कर दिए; कुछ का इन लोगों से सामना हुआ। उनसे कहा गया कि वे लोगों के बीच जाकर खुली घोषणा करें कि वे गैर ज़रूरी इंजेक्शन और सेलाइन नहीं देंगे। साथ ही हरेक डॉक्टर के लिए यह ज़रूरी कर दिया गया कि वे अपनी क्लीनिक/अस्पताल पर दवाइयों, सेलाइन आदि के अविवेकपूर्ण उपयोग की खिलाफत करते पोस्टर लगाएंगे।

कुछ चिकित्सकों ने प्रदर्शन कर रहे कस्बाइयों से सहमति जतलाई और उन्हें अपना समर्थन दिया। कुछ ने सुरक्षात्मक रवैया अपनाया लेकिन फिर भी अपना समर्थन दिया ही। इन डॉक्टरों से मिलने के बाद इन लोगों ने गवर्नमेंट कॉटेज हॉस्पिटल का रुख किया। इन प्रदर्शनकारियों ने दवाइयों की अनुपलब्धता, परिवहन के साधनों की कमी, मरीज़ों से मनमाना भुगतान वसूलना और आदिवासी मरीज़ों के साथ दुर्व्यवहार जैसे सवाल डॉक्टरों और उनके सहायकों पर दागे। लोगों ने अपने अनुभव बताए और चिकित्सकों से उनका स्पष्टीकरण मांगा। इन वॉलण्टियर्स ने एक चार्ट तैयार किया जिसमें विभिन्न अस्पताली स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की वैधानिक दर लिखी गई थी।

इतना ही नहीं मरीज़ों के लिए भी एक पोस्टर था जिनमें लिखा था कि वे किसी भी तरह का भुगतान डॉक्टर या अन्य सहायकों को न करें; भुगतान केवल कार्यालय में ही करें तथा उस भुगतान की पर्ची भी लें। इन दोनों पोस्टरों को जगह-जगह पर प्रदर्शित किया गया। कॉटेज हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ ने यकीन दिलाया कि कई सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और किसी भी तरह की गैरवाजिब फीस नहीं ली जाएगी।

यह 'आरोग्य-पदयात्रा' या कहिए हेल्थमार्च दो दिन पहले दहाणु तालुका के एक छोटे से कस्बे कासा में सम्पन्न हुए एक अभियान का बड़ा रूप थी। कासा में भी कुछ सक्रिय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के साथ तकरीबन अस्सी लोगों ने निजी चिकित्सकों से बातचीत की। उनके दवाखानों पर पोस्टर चिपकाए और उनकी डिग्रियां भी जांची। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि अब वे एक सेलाइन बॉटल के लिए अधिक से अधिक पचास रुपए ही लेंगे। और सेलाइन भी तब लगाएंगे जब वह एकदम ज़रूरी हो जाएगी। यह पदयात्रा गांव के सरकारी अस्पताल में खत्म हुई जहां डॉक्टरों से तीखे सवाल किए गए।

क्यों मरीज़ों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं? सरकारी अस्पतालों में क्यों दवाइयों का अकाल पड़ा रहता है? क्यों सरकारी अमला हर सेवा के लिए पैसा झटकने की फिराक में रहता है? क्यों आदिवासी मरीज़ों से दुर्व्यवहार किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) के डॉक्टरों से पूछा गया कि क्यों नर्सें (ए.एन.एम.) गांव की कुछ खास बस्तियों में नहीं पहुंचतीं? क्यों टीकाकरण नियमित तौर पर नहीं होता?

काश्तकारी संगठन के लोगों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों से काफी बातचीत की। डॉक्टरों ने यकीन दिलाया कि अब वे मरीज़ों को अस्पताल से ही दवाइयां मुहैया